मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

बधावन भाईयों ने बैंकों को लगाया 34615 करोड़ रुपये का चूना 2
विरोधियों पर दमन चक्र चलाने से बाज आए सरकार 4
कोलम्बिया राष्ट्रपति चुनाव: लैटिन जनता ने लिखी नई इबारत 5
बेरोजगारी बढ़ाना लक्ष्य बना लिया है सरकार ने 6
हल्की सी बारिश ने ही खोल दी प्रशासन की पोल 8

वर्ष 36 | अंक 33 | फरीदाबाद | 26 जून-2 जुलाई 2022 | फोन-8851091460 | 5.00 ₹

सरकारी भोंपुओं के लिए फौज की नौकरी रोजगार नहीं

देश सेवा के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट सेवा

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

एक कुशल सेल्समैन की भांति अपनी अग्निपथ योजना को बेचने के लिये मोदी ने अपने तमाम भोंपूओं को लगा रखा है। तमाम बड़े उद्योगपति, तीनों सेनाध्यक्ष तथा तमाम लगुए-भगुए इस योजना को बेचने के लिये तरह-तरह के कुतर्क आये दिन पेश कर रहे हैं। उनमें से एक कुतर्क यह भी है कि फौज की नौकरी कोई रोजगार नहीं, यह तो देश सेवा है। चलो मान लेते हैं कि यह केवल देश सेवा है, तो क्या मोदी जी अपने रोजगार के आंकड़ों में अग्निवीरों को नहीं गिनेंगे? बिल्कुल गिनेंगे, आगामी डेढ साल में दस लाख नौकरी देने का जो झांसा दिया है, उसमें डेढ़ दो लाख तो अग्निवीर ही गिने जायेंगे।

सरकारी भोंपू यह भी बताते हैं कि इजराइल में हर लड़के-लड़की को अनिवार्य रूप से डेढ़ साल फ़ौज की नौकरी करनी होती है। इसी तरह उत्तर व दक्षिण कोरिया आदि कई देशों में तमाम नागरिकों के लिये कुछ समय के लिये फ़ौज की नौकरी अनिवार्य है। ब्रिटेन में युवराज को राजगद्दी पर बैठने से पहले फ़ौज की नौकरी करना अनिवार्य है। इसी शर्त को निभाते हुए कुछ वर्ष पूर्व प्रिंस फिलिप बतौर फ़ौजी अफगान युद्ध लड़ने भी पहुंचे थे। लेकिन ये भोंपू यह नहीं बताते कि फ़ौज की नौकरी के दौरान तथा उसके बाद उन्हें क्या-क्या उपलब्ध कराया जाता है?

यहां बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यह देश सेवा उन गरीबों के जिम्मे ही क्यों है जिनके पास रोजी-रोटी का कोई अन्य विकल्प नहीं है? तमाम बड़े उद्योगपतियों व राजनेताओं के बेटों को इस सेवा का अवसर क्यों नहीं दिया जाता? अमितशाह का नालायक बेटा क्रिकेट बोर्ड का सचिव बनकर करोड़ों बटोर सकता है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का बेटा अमेरिका से एलएलएम की डिग्री ला सकता है और मुकेश अम्बानी का बेटा बेठे-बिठाये खरबोंपति बन सकता है; इन्हें भी तो जरा दो-चार साल के लिये अग्निपथ पर चलाकर देश सेवा का मौका दिया जाना चाहिये।

वैसे गम्भीरता से देखा जाय तो फ़ौज की नौकरी कोई रोजगार हो भी नहीं सकती। फौज़ कोई उत्पादक प्रक्रिया नहीं निभाती। इसे दुश्मन से लड़ने के लिये तैयार रखा जाता है। मान लो यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान अखंड भारत के अंग बन जायें तो इन तीनों देशों में सेना की क्या जरूरत रह जायेगी? जाहिर है कि ऐसे में तमाम फ़ौजियों को देश के लिये उत्पादक सेवाओं में लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत व जनता को सम्पन्न किया जा सकेगा।

शासक वर्गों ने बड़ी कुटिलता के साथ देश में एक ऐसा युवा वर्ग तैयार कर लिया है जो फ़ौज एवं अर्धसैनिक बलों में रोजगार तलाशने के अलावा और किसी काम का नहीं रह गया है। हां, यदि उसे तहसील जैसे महकमे में चपरासी की या पुलिस में सिपाही की नौकरी मिल जाये तो वह फ़ौज की तरफ़ झांके भी न। अपनी कुटिल नीतियों के चलते शासक वर्गों ने देश की जनता को असली उत्पादक रोजगारों से वंचित कर दिया है। तमाम सरकारी शिक्षण संस्थानों, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तथा बड़े राष्ट्रीय प्रोद्योगिक संस्थानों (आईआईटी) में आधे से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। इसी तरह अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टॉफ़ के 70 प्रतिशत तक पद खाली पड़े हैं। संक्षेप में केन्द्र व राज्य सरकारों के करीब डेढ करोड़ पद आज के दिन खाली पड़े हैं।

साधन सम्पन्न लोग अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ाने के बाद उच्च शिक्षा के लिये विदेशों में भेज देते हैं जिस पर देश की विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में खर्च हो जाती है। इन हालात में गरीब एवं वंचित परिवारों के बच्चे शिक्षा व चिकित्सा बल्कि पौष्टिक भोजन तक से भी महरूम रह जाते हैं। इनमें से जो थोड़े-बहुत जैसे-तैसे दसवीं-बारहवीं तक पढ़ कर निकल पाते हैं उनके सामने शासक वर्ग ने उस फ़ौज की नौकरी के अलावा कोई वैकल्पिक रोजगार छोड़ा ही नहीं जिसे वह रोजगार मानने से ही इनकार करता है। देशभक्ति की चाश्नी में लपेट कर फौज की कठिनतम एवं जोखिम भरी नौकरी करना उसकी मजबूरी बना दी गई है।

जनरल पुरी अपनी पे स्लिप तक नहीं देखते

बतौर सरकारी भोंपू लेफ्टीनेंट जनरल एवं रक्षा मंत्रायल में विशेष सचिव पुरी ने प्रेस को सम्बोधित करते हुए एक बड़ा झूठ यह भी बोला कि वे तो कभी अपनी पे स्लिप देखते ही नहीं। जरूरत भी क्या है, लाखों रुपये का वेतन हर महीने बैंक में पहुंच जाता है, घर व चूल्हे-चौके तक सारा खर्च सेना के खाते से चुपचाप उनके यहां पहुंच ही जाता है। वेतन से कहीं ज्यादा खर्चे तो सेना के खाते से वेसे ही मिल जाते हैं। वेतन तो केवल उनकी जमा पूंजी में बढोत्तरी करने के लिये ही होता है।

इसके बरक्स जिन युवाओं को वे उक्त उपदेश दे रहे हैं उनकी तो सारी गुजर-बसर ही नौकरी से मिलने वाले वेतन पर निर्भर है।

पूर्व सेनाध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री वीके सिंह ने तो पल्टी मारने में कमाल ही कर दिया। जो पहले दिन अग्निपथ के बारे में कुछ बोलने से बचने के लिये कह रहे थे कि वे तो इसके बारे में अभी कुछ जानते ही नहीं, अगले ही दिन वे इसके बड़े वकील बन गये। ये वही वीके सिंह हैं जो सेवा निवृत्ति के वक्त एक वर्ष की सेवा और प्राप्त करने के लिये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गये थे। आज वही मात्र चार साल की सेवा को पर्याप्त बता रहे हैं।

प्रदर्शनों में हिंसा व तोड़-फ़ोड़

अग्निपथ को लेकर हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, आगजनी व तोड़-फ़ोड़ को लेकर तमाम लोगों ने प्रदर्शन का तो समर्थन किया लेकिन आगजनी तोड़-फ़ोड़ व हिंसा का विरोध किया। सभी ने इसे राष्ट्रीय क्षति बताया है यानी राष्ट्र की संपत्ति का नुक्सान बताया है। इन सभी ने शांतिपूर्वक आंदोलन एवं प्रदर्शन की वकालत की है।

सत्य तो यह है कि कोई भी व्यक्ति इतनी फुर्सत में नहीं होता कि वह आन्दोलन एवं प्रदर्शन आदि में अपना समय व्यर्थ गंवाये। यह तो सरकार की नीतियां होती हैं जो उसे आन्दोलन एवं प्रदर्शन के लिये बाध्य करती हैं। जब कोई सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भाषा को न समझे और ढीठ बनकर अपनी जनविरोधी नीतियों पर कायम रहे तो आन्दोलनकारियों को मजबूरन तोड़-फ़ोड़ व आगजनी का रास्ता अख्त्यार करना पड़ता है। उनके पास पथराव से बड़ा कोई हथियार होता नहीं है। हिंसा करने के तमाम हथियार लाठी, गोली, बंदूक, टीयर गैस आदि जैसे तमाम साधन तो सरकारी दस्तों के पास होते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रदर्शनकारी घायल भी होते हैं और जान से भी मरते हैं।

तर्क दिया जाता है कि ये तमाम संपत्तियां बस, रेल, सरकारी भवन आदि सब कुछ तो जनता का अपना ही है। फ़िर इसे जला कर जनता अपना ही नुकसान क्यों कर रही है? इसके जवाब में आग लगाने वाले उग्र युवा तर्क देते हैं कि यदि ये बसें व रेलें जनता की हैं तो कोरोना के वक्त जब लाखों लोग सैंकड़ों-हजारों मील पैदल चल रहे थे तो ये रेलें व बसें कहां थीं? आज भी सरकार ने आधी से अधिक रेल सेवायें बंद कर रखी हैं। ओर जो चल भी रही हैं तो उन पर मनमाने भाड़े लागू कर रखे हैं। दूसरा तर्क यह भी दिया जाता है कि जो चीज़ जनता की है और जनता ही उसे जला रही है तो सरकार क्यों परेशान हो रही है?

शांतिपूर्ण आंदोलन का एक ताज़ातरीन उदाहरण आज भी मौजूद है। करीब 1000 युवाओं का जत्था तिरंगा हाथ में लेकर नागपुर से दिल्ली की ओर पैदन बढ़ रहा है। इन युवाओं की मांग केवल इतनी सी है कि सरकार द्वारा 2018 में केन्द्रीय सुरक्षा बलों के लिये निकाली गई भर्तियों में जब वे उत्तीर्ण हो चुके हैं तो उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? बड़ी वाजिब मांग है, परन्तु सुनता तो कोई नहीं और मीडिया में भी उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही। उनकी बात तक कोई करने को तैयार नहीं। हां, यदि उन्होंने कुछ बड़ी हिंसक वारदातें कर दी होतीं तो उनका आन्दोलन भले ही फेल हो जाता परन्तु मीडिया तुरन्त उनकी कवरेज करता।

जब कमजोर एवं पीड़ित की बात कोई नहीं सुनता और जाबर के गले तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता तो वह आक्रोश एवं क्षोभ में अपनी नसें काट लेगा या फंदे पर लटक जायेगा या अपने को आग लगा कर मर जायेगा। लगभग ऐसी ही कुछ स्थिति आज अग्निवीरों की भी है।